कोहरे के बाद रोशनी की उम्मीद

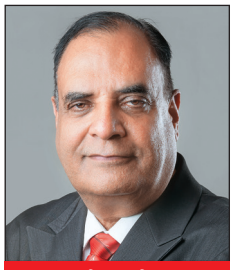

आलोक मेहता

प्रकृति का नियम है। कोहरा अपरिहार्य है, लेकिन देर-सबेर सूरज के साथ सुहानी सुबह और रोशनी की उम्मीद भी सही होती है। भारत में अंधकार, कोहरे, आंधी-तूफान, प्राकृतिक-राजनीतिक भूचाल, आर्थिक संकट के दौर आते-जाते रहे हैं। अपनी पत्रकारिता के लगभग 45 वर्षों के दौरान कई बार हमने यह सवाल उठाए और सुने हैं, 'इस कठिन दौर से क्या हमें निजात मिल पाएगी?' कुछ लोग अधिक निराशावादी होते हैं और अंधविश्वास की तरह डराते हैं, 'अब पतन की पराकाष्ठा हो गई। कहीं कुछ ठीक नहीं होगा।' लेकिन मुझे ऐसे विचारकों, संपादकों, सामाजिक-राजनीतिक नेताओं तथा आर्थिक विशेषज्ञों के संपर्क में रहने के अवसर मिले, जिन्हें समय के साथ अनुकूल परिस्थितियां आने और देश के आगे बढ़ते रहने का विश्वास रहा। इसलिए आज भी ऐसा सवाल उठने पर यही उत्तर गूंजता है- 'सुबह जरूर आएगी।' यह याद रखना होगा कि सुबह पूरब दिशा में पहले आती है। अरुणाचल-असम, बंगाल से केरल तक नए साल में राजनीतिक हवा के साथ प्रगति की नई सुबह के लोकतांत्रिक प्रयास होंगे। दावे और वायदे हर राजनीतिक दल, सत्ताधारी अथवा विपक्ष के होते हैं। इस संदर्भ में जनवरी, 1959 में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई कुछ बातें याद दिलाना उचित है। नेहरू ने कहा था, 'याद रखिए, दिल्ली हिंदुस्तान का और दुनिया का एक खास शहर है और आप तथा हम जो दिल्ली में रहते हैं, एक मायने में खुशनसीब हैं। लेकिन दिल्ली शहर हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान की राजधानी है। हिंदुस्तान तो लाखों गांवों का है और जब तक हिंदुस्तान में गांव नहीं उठते, नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास (अब चेन्नई) हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें इन गांवों को आगे बढ़ाने की बात ध्यान रखनी है।'

पांच दशकों के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। महानगरों के साथ बहुत से शहर एक हद तक 'स्मार्ट' हो गए हैं। 'जेंटलमेन' कहलाने वालों की संख्या भी लाखों-करोड़ों में पहुंच गई है लेकिन हजारों गांव अब भी बेहाल हैं। असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल तो दूर हैं, राजधानी दिल्ली में विधायकों और सांसदों की सुख-सुविधाओं पर बहस के साथ बाहरी दिल्ली के गांवों की दशा पर चर्चा या प्रभावशाली मीडिया में विस्तृत रिपोर्ट नहीं दिखती। गुड़गांव या नोएडा के कुछ इलाके यूरोपीय देशों के उपनगरों की तरह आधुनिक और संपन्न दिखते हैं। लेकिन नजफगढ़, नांगलोई जैसे इलाके दिल्ली के अभिन्न अंग होते हुए भी बंगाल-बिहार के गांवों से बदतर स्थिति में दिखाई देते हैं।

दिल्ली में हरकिशनलाल भगत, मदनलाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा जैसे कांग्रेसी-भाजपाई नेतृत्व रहते हुए दिल्ली के गांवों की सुविधाओं के लिए कुछ काम होते रहे, लेकिन अब कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी के अधिकांश नेताओं की प्राथमिकता गांव नहीं आधुनिक बाजार में वाई-फाई की सुविधाएं, मेट्रो रेल, चमचमाती और जगमगाती सड़क और जनता को मोहित करते रहने की है। लखनऊ, पटना, रांची, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूरु जैसी राजधानियों का प्रशासनिक तंत्र इसी 'स्मार्ट' मूड को महत्व दे रहा है। ममता, नीतीश, अखिलेश जैसे नेताओं के समक्ष भी संरक्षकों- विधायकों की बड़ी मांग 'स्मार्ट सिटी' में हिस्सेदारी की रहती है। नीतीश कुमार को बड़ी संख्या में गांवों की सड़कों तथा बिजली की सुविधाएं पहुंचाने का लाभ विधानसभा चुनाव में भी मिला। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने सड़कों का जाल बिछाया। लेकिन गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब भी बड़े पैमाने पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रयास करने होंगे।

केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षा-स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोत्तरी तो दूर कुछ कटौती ही की है। न्यूनतम मजदूरी दिलाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए रखा बजट दिसंबर में ही खत्म हो गया। मजदूरी करके बच्चों को साक्षर बनाने की इच्छा रखने वाले मां-बाप भी संकट में हैं। सरकार का तर्क है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अधिक धनराशि मिल रही है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकारों को अपने वित्तीय संसाधनों से अधिक खर्च करना चाहिए। इस तकनीकी दलील के बजाय केंद्र सरकार और संसद को गांवों में शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए विशेष योजना, बजट और समयबद्ध क्रियान्वयन पर फैसला करना चाहिए। आखिरकार, जापान ने 40 वर्षों के शिक्षा अभियान के बाद देश को आधुनिक टेक्नोलॉजी और निर्यात के बल पर तेजी से आगे बढ़ाया। याद करें 'मेड इन जापान' के सामान एशिया से अधिक यूरोप और अमेरिका के बाजार में छा गए थे। पिछले वर्षों के दौरान 'मेड इन चाइना' ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। चीन से मुकाबले के लिए भारत को क्रांतिकारी प्रयास करने होंगे। गांवों को बेहतर शिक्षित और स्वस्थ बनाए बिना 'मेक इन इंडिया' का स्वप्न कैसे साकार होगा। केंद्र तथा राज्य सरकारें इन दिनों बजट बनाने में जुटी हुई हैं। सड़कों के साथ पीने योग्य स्वच्छ पानी, सिर छिपाने लायक छत, स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था को प्राथमिकता बजट में ही मिलनी चाहिए।

जेंटलमेन कहलाने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच गई है लेकिन हजारों गांव अब भी बेहाल हैं। असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल तो दूर हैं दिल्ली के गांवों की दशा पर चर्चा भी मीडिया में नहीं दिखती।

राजनीतिक टकराव के दौर में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, राममनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, ईएमएस नंबूदिरीपाद गांवों की कायापलट के मुद्दे पर समान विचार रखते थे। फिर वर्तमान राजनेता इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति क्यों नहीं बना सकते हैं।

www.outlookhindi.com